न्यायमूर्ति के. एस. तिवाना और प्रीतपाल सिंह के समक्ष

गुरदयाल सिंह और अन्य, — *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य — *उत्तरदाता*

आपराधिक पुनरीक्षण सं. 613 *सन्* 1986

सितंबर 12, 1986

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (1985 का XLVI) - धारा 6, 9, 10(1) - शस्त्र अधिनियम (1878 का XI) - धारा 25 - भारतीय दंड संहिता (1860 का XLV) - धारा 307 और 323 - आरोपी आतंकवादी अधिनियम के तहत अधिसूचित क्षेत्र में शस्त्र अधिनियम और दंड संहिता के तहत किए गए अपराधों के लिए सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई पर - शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध आतंकवादी अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय है - संहिता के तहत अपराध इसके अंतर्गत नहीं आते हैं - संपूर्ण मुकदमे को आतंकवादी अधिनियम के तहत गठित निर्दिष्ट न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करने वाला अभियोजन - संहिता के तहत किए गए अपराध शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध से जुड़े नहीं हैं - कोई आरोप नहीं है कि बरामद किए गए हथियार का उपयोग संहिता के तहत अपराध करने में किया गया था - शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध - क्या विशेष रूप से आतंकवादी अधिनियम के तहत नामित न्यायालय द्वारा विचारणीय है - सत्र न्यायालय - क्या संहिता के तहत अपराधों के मुकदमे को नामित न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार क्षेत्र है।

अभिनिर्णित, कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1985 की धारा 6(1) के अनुसार शस्त्र अधिनियम 1878 के तहत हर अपराध राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी भी क्षेत्र में प्रतिबद्ध इस धारा के तहत दंडनीय है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध आतंकवादी अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय हैं, इसलिए आतंकवादी अधिनियम की धारा 9 शस्त्र अधिनियम के तहत किए गए प्रत्येक अपराध पर लागू होती है और आवश्यक रूप से नामित न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार, नामित न्यायालय को निस्संदेह शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामले की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए इस तरह के अपराध की सुनवाई विशेष रूप से आतंकवादी अधिनियम के तहत गठित नामित न्यायालय द्वारा की जाती है।

(पैरा 9 और 10)

अभिनिर्णित, कि आतंकवादी अधिनियम की धारा 10(1) को पढ़ने से पता चलता है कि इसके आवेदन को आकर्षित करने के लिए तीन शर्तें आवश्यक हैं। सबसे पहले, नामित न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अपराध की सुनवाई करनी चाहिए। दूसरा, आरोपी पर उसी मुकदमे में अन्य अपराध करने का आरोप लगाया जाना चाहिए और तीसरा, उन अन्य अपराधों को नामित न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध से जोड़ा जाना चाहिए। हालाँकि, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अभियुक्त किसी आतंकवादी या विघटनकारी कृत्य के दोषी थे और न ही यह कि शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध के आरोपी अभियुक्त ने अपराध के दौरान हथियार का इस्तेमाल किया था, दंड संहिता के तहत अपराध और यह नहीं कहा जा सकता कि शस्त्र अधिनियम एक ही मुकदमे की विषय वस्तु है और न ही यह कहा जा सकता है कि शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध संहिता के अंतर्गत अपराध से सख्ती से जुड़ा हुआ है। आतंकवादी अधिनियम की धारा 10(1) का सक्षम प्रावधान जो नामित न्यायालय को किसी अन्य अपराध की सुनवाई करने का अधिकार देता है जिसके लिए आरोपी पर उसके द्वारा विशेष रूप से विचारणीय अपराध के साथ एक ही मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है। अत: इस स्थिति में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आकर्षित नहीं होते थे। संहिता के तहत अपराधों को अंजाम देने में पूरी तरह से सक्षम और ऐसे अपराधों के मुकदमे को नामित न्यायालय में स्थानांतरित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(पैरा 11)

मामले में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए इस मामले को 29 मई, 1986 को माननीय श्री न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी द्वारा एक खंड न्यायपीठ को भेजा गया था। माननीय श्री न्यायमूर्ति के. एस. तिवाना और माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतपाल सिंह की खंडपीठ ने अंततः 12 सितंबर, 1986 को मामले का निपटारा कर दिया।

श्री के.के. चोपड़ा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार के 16 अप्रैल, 1986 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए यह याचिका, जिसमें आदेश दिया गया था कि मामले को कानून के अनुसार सुनवाई के लिए नामित न्यायालय भिवानी में भेजा जाए। अभियुक्त गुरदयाल सिंह को उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए और अभियुक्त गुरमुख को 30 अप्रैल, 1986 को नामित न्यायालय, भिवानी के समक्ष पेश किया जाए।

जे. एस. मान, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए ।

कमल शर्मा, ए.ए.जी, हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए ।

निर्णय

न्यायमूर्ति प्रीतपाल सिंह -

(1) याचिकाकर्ता गुरदयाल सिंह और गुरमुख सिंह भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 307 और 323 के तहत सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय में प्रतिबद्ध थे। मुकदमा विद्वक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार की अदालत में शुरू हुआ। उचित आरोप तय किए गए और अभियोजन साक्ष्य का हिस्सा दर्ज किया गया।

(2) याचिकाकर्ता गुरमुख सिंह पर इस आरोप पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अलग से मुकदमा चलाया गया था कि जब उन्हें मुख्य मामले में गिरफ्तार किया गया था तो उनके पास एक एकल बैरल वाली बंदूक पाई गई थी, जिसका लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था और नवीनीकरण नहीं किया गया था। इस मामले की सुनवाई भी हिसार के विद्वक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी।

(3) जब 16 अप्रैल, 1986 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 307 और 323 के तहत मामले में साक्ष्य का एक हिस्सा दर्ज किया गया था, तो अभियोजन पक्ष की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था कि शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत यह मामला अन्य मामले के साथ-साथ आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1985 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के तहत गठित नामित न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। विद्वक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आवेदन स्वीकार कर लिया और उसी तारीख के आदेश के तहत दोनों मामलों को नामित न्यायालय, भिवानी को भेज दिया।

(4) याचिकाकर्ताओं ने मामलों को नामित न्यायालय में स्थानांतरित करने के विद्वक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ तत्काल पुनरीक्षण याचिका दायर की, इस दलील पर कि ये मामले विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं और नामित न्यायालय के पास मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस न्यायालय के विद्वक एकल न्यायाधीश, जिन्होंने पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की, ने इसमें शामिल बिंदु के महत्व पर विचार करते हुए याचिका को एक बड़ी पीठ द्वारा तय करने के लिए संदर्भित किया। यह इन परिस्थितियों में है कि अब हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

(5) हम सबसे पहले शास्त्र अधिनियम के तहत मामले से निपटेंगे। विद्वक याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह मामला अधिनियम के दायरे में नहीं आता है और इसलिए इसे सुनवाई के लिए नामित न्यायालय में नहीं भेजा जा सकता है। हम इस विवाद को कायम रखने में असमर्थ हैं। अधिनियम की प्रस्तावना से पता चलता है कि इसे आतंकवादी और

विघटनकारी गतिविधियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम का दूसरा भाग आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों से निपटने के लिए दंड और खजाने से संबंधित है। इस भाग में धारा 3 से 6 शामिल हैं। आतंकवादी कृत्य क्या है, इसे धारा 3 की उप-धारा (1) में परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि "जो कोई भी स्थापित कानून के अनुसार सरकार को डराने या आतंक फैलाने के इरादे से लोग या लोगों का कोई भी वर्ग या लोगों के किसी भी वर्ग को अलग-थलग करने के लिए या लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या आग्नेयास्त्रों का उपयोग करके कोई कार्य या चीज करता है या अन्य घातक हथियार या जहर या हानिकारक गैसें या अन्य रसायन या खतरनाक प्रकृति के कोई अन्य पदार्थ (चाहे जैविक या अन्यथा) जिससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या उसे चोट लगने की संभावना हो। व्यक्तियों या संपत्ति को क्षति या विनाश या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान, एक आतंकवादी कृत्य है।" उपधारा (2) आतंकवादी कृत्य करने के लिए सज़ा निर्धारित करती है। उपधारा (3) उस व्यक्ति को दी जाने वाली सजा का प्रावधान करती है जो आतंकवादी कृत्य की साजिश रचता है या करने का प्रयास करता है।

(6) धारा 4 की उपधारा (2) "विघटनकारी गतिविधि" शब्द को परिभाषित करती है। निम्नलिखित नुसार:

"उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, "विघटनकारी गतिविधि" इसका अर्थ है की गई कोई कार्रवाई, चाहे कार्य द्वारा या भाषण द्वारा या किसी अन्य साधन के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से:

(i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाता है, बाधित करता है या बाधित करने का इरादा रखता है; या

(ii) जिसका उद्देश्य भारत के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण या संघ से भारत के किसी भी हिस्से के अलगाव के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दावा करना या उसका समर्थन करना है।

स्पष्टीकरण.--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए--

(क) "अधिवेशन" भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी विदेशी देश के किसी भी दावे को स्वीकार करना शामिल है; और

(ख) "अलगाव" इसमें यह निर्धारित करने के लिए किसी भी दावे का दावा शामिल है कि भारत का एक हिस्सा संघ के भीतर रहेगा या नहीं।

धारा 4 की उपधारा (1) विघटनकारी गतिविधियों के लिए दंड का प्रावधान करती है।

(7) धारा 5 पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियों से संबंधित है। यह अनुभाग हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है।

(8) इसके बाद धारा 6 आती है जिस पर इस मामले के निर्णय के लिए स्पष्ट रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"6. (1) यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी भी क्षेत्र में शस्त्र अधिनियम, 1959, विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, या ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है, के तहत बनाए गए ऐसे किसी प्रावधान या किसी नियम का उल्लंघन करता है वह, उपरोक्त किसी भी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, दंडनीय होगा एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है या, यदि उसका इरादा किसी आतंकवादी या व्यवधान की सहायता करना है, तो मृत्युदंड या एक अवधि के लिए कारावास- जो तीन साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे आजीवन कारावास की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है;, और जुर्माना भी देना होगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई भी व्यक्ति जो किसी कानून, नियम या आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उकसाता है, या उकसाने का प्रयास करता है, या उल्लंघन की तैयारी के लिए कोई कार्य करता है, उसे उस प्रावधान का उल्लंघन माना जाएगा।"

(9) अधिनियम के तहत नामित न्यायालयों का गठन धारा 7 के आधार पर किया जाता है। धारा 9(1) में कहा गया है कि "संहिता में किसी भी बात के बावजूद, (जिसका अर्थ है धारा 2(1) में परिभाषित आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध की सुनवाई केवल उस नामित न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर यह किया गया था।" यह धारा यह स्पष्ट करती है कि कोई भी अपराध जिसके लिए अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत सजा का प्रावधान है, उसकी सुनवाई विशेष रूप से नामित न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। ऊपर प्रस्तुत धारा 6(1) के अनुसार राज्य द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी

भी क्षेत्र में किया गया शस्त्र अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध इस धारा के तहत दंडनीय है। माना जाता है कि धारा 6 वर्तमान मामले पर लागू होती है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रावधान के तहत हरियाणा के क्षेत्रों पर लागू होने वाले शस्त्र अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू करने की एक अधिसूचना है। इसलिए, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि धारा 6 के आधार पर हरियाणा राज्य में शस्त्र अधिनियम के तहत किया गया प्रत्येक अपराध इस धारा के तहत दंडनीय है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 9 के तहत, हरियाणा में शस्त्र अधिनियम के तहत किए गए अपराध की सुनवाई विशेष रूप से अधिनियम के तहत गठित एक नामित न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।

(10) विद्वक याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 6 को केवल शस्त्र अधिनियम और धारा में उल्लिखित कुछ अन्य अधिनियमों के तहत किए गए अपराधों के संबंध में बढ़ी हुई सजा प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्र अधिनियम की धारा 25 शास्त्र अधिनियम के तहत ही दंडनीय है और इस कारण से अधिनियम की धारा 9 का कोई उपयोग नहीं होता है। हम इस विवाद से प्रभावित नहीं हैं। अधिनियम एक स्व-निहित क़ानून है जो प्रस्तावना में स्पष्ट विशेष उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया है। यह निर्माण का एक नियम है कि किसी क़ानून के सभी प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए, और इसलिए, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह किसी क़ानून को सामंजस्यपूर्ण ढंग से लागू करे। अधिनियम की धारा 6 अधिनियम का एक अभिन्न अंग है और इसका उद्देश्य केवल उसमें उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों के तहत किए गए अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा प्रदान करना नहीं है। इस धारा में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में धारा में उल्लिखित अधिनियमों के तहत किए गए अपराध, जिसमें शस्त्र अधिनियम भी शामिल है, उन अधिनियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, इस धारा के तहत दंडनीय हैं। दूसरे शब्दों में, उन अधिनियमों के तहत अपराध करने से संबंधित प्रावधानों को सजा के प्रयोजनों के लिए अधिनियम में शामिल किया गया है। चूँकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कुछ क्षेत्रों में शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों को धारा 6 के तहत दंडनीय बनाया गया है, इसलिए धारा 9 स्पष्ट रूप से लागू हो जाती है और शस्त्र अधिनियम के तहत किए गए प्रत्येक अपराध की सुनवाई आवश्यक रूप से नामित न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। इसलिए, नामित न्यायालय को याचिकाकर्ता गुरमुख सिंह के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र निस्संदेह जब्त कर लिया गया है।

(11) अब हम भारतीय दंड संहिता के तहत दूसरे मामले की ओर बढ़ते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 और 323 के तहत मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के लिए नामित न्यायालय में नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि उन्हें स्वयं उस मामले पर विचार करने का उचित क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि वह खुद को अधिकार क्षेत्र से अलग नहीं कर सकता था और नामित

न्यायालय से इसकी कोशिश करने के लिए कहने में सक्षम नहीं था। जवाब में विद्वक राज्य के अधिवक्ता का तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 10 नामित न्यायालय को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत उपरोक्त मामले के साथ इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार देती है। धारा 10(1) इस प्रकार है:

> "10(1) किसी भी अपराध की कोशिश करते समय एक नामित न्यायालय किसी अन्य अपराध की भी सुनवाई कर सकता है जिसके साथ आरोपी पर संहिता के तहत उसी मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से जुड़ा हुआ है।

इस प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि इसके आवेदन को आकर्षित करने के लिए तीन शर्तें आवश्यक हैं। सबसे पहले, नामित न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अपराध की सुनवाई करनी चाहिए। दूसरा, आरोपी पर उसी मुकदमे में अन्य अपराध करने का आरोप लगाया जाना चाहिए, और तीसरा, उन अन्य अपराधों को नामित न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध से जोड़ा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में दूसरी और तीसरी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, जाहिर तौर पर, अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 भारतीय दंड संहिता के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामले में आकर्षित नहीं होती हैं। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं पर न तो कोई आतंकवादी या विघटनकारी कार्य करने का आरोप है, न ही शस्त्र अधिनियम के तहत कोई अपराध है, याचिकाकर्ता गुरमुख सिंह पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसमें अधिनियम की धारा 6 लागू होता है। दोनों मामलों की सुनवाई विद्वक अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में अलग-अलग चल रही थी। हालांकि भारतीय दंड संहिता के तहत मामले की जांच के दौरान गुरमुख सिंह याचिकाकर्ता से कथित तौर पर एक बंदूक बरामद की गई थी, जिसका लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि इस बंदूक का इस्तेमाल अपराध में किया गया था। अपराध के दौरान बंदूक का इस्तेमाल करने के मामले में गुरमुख सिंह पर भारतीय दंड संहिता के तहत शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध एक ही मुकदमे का विषय नहीं हैं, न ही यह छापा जा सकता है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध सीधे भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों से जुड़ा हुआ है। इसलिए, हमारी दृढ़ राय है कि अधिनियम की धारा 10(1) का सक्षम प्रावधान, जो नामित न्यायालय को किसी अन्य अपराध की सुनवाई करने का अधिकार देता है जिसके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया जा सकता है; उसके द्वारा विशेष रूप से विचारणीय अपराध के साथ एक ही मुकदमा, वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भारतीय दंड संहिता के तहत मामले की सुनवाई करने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे और उनके पास इसे नामित न्यायालय में स्थानांतरित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 194 के तहत खंड के विद्वक सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के लिए उन्हें सौंप दिया गया था। इसलिए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र केवल मामले की सुनवाई तक ही सीमित

था, और इसे नामित न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने तक इसका विस्तार नहीं था। नामित न्यायालय अधिनियम की धारा 10 की अनुपयुक्तता के कारण शस्त्र अधिनियम के तहत मामले के साथ इस मामले की सुनवाई भी नहीं कर सकता है।

उपरोक्त कारणों से, विद्वक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार के दिनांक 16 अप्रैल, 1086 के आक्षेपित आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 और 323 के तहत मामला विद्वक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार की अदालत में चलाया जाएगा। नामित न्यायालय, भिवानी, तुरंत मामले के रिकॉर्ड अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार की अदालत को लौटा देगा। हालाँकि, नामित न्यायालय, भिवानी, शस्त्र अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई करेगा।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

रूहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा